

एक नजर

मुसलमानों ने कहा-न दूरी है न
खाई है मोदी हमारा भाई है

रायपुर, 03 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वावधान में बुधवार को राजधानी के नार घड़ी चौक पर संसद में प्रस्तुत वक्फ बोर्ड संशोधन का आदिवासी करके स्वागत किया गया। इसे गरीब मुसलमानों के हते में उठाया गया एक ऐतिहासिक आदिवासी कदम बताते हुए मोर्चा की ओर से प्रश्नामंडी नोरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिंजु को बधाई दी। इस भौमि पर मोर्चा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने -न दूरी है - न खाई है - मोदी हमारा भाई है - के गणनामंडी नारे लाकार मिजाजियाँ भी बांटी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चों के पदाधिकारियों ने बताया कि आज जो वक्फ संशोधन लिया गया है, उससे घोटालों पर रोक लगेगी और जो अवैध कब्जाधारी है, उन पर लापाम लगेगी। ये अवैध कब्जाधारी अरबों रुपए की संपत्तियों पर सालों से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उन पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर को साथ में शामिल किया गया है, ताकि कलेक्टर के द्वारा राजस्व मालों के निटारों जल्दी हों और राजस्व रिकॉर्ड सही कर उनका अतिक्रमण हटाया जा सके। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि वक्फ वह अतिक्रमण है तो वहाँ पर अवैध संख्यकों के शैक्षणिक, अर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वहाँ स्कूल, अस्पताल बनाए जाएं। इन अतिक्रमणों के हटाने से वक्फ संपत्तियों से सरकारी खाजाने में 12 हजार करोड़ रुपए की आवक होगी जो अभी महज 162 करोड़ रुपए है। इस वक्फ विधेयक में पहली बार दो महिला सदस्यों को नियुक्त का प्रवाधन करके नारी सशक्तीकरण की दिशा में भी केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी कार्य किया है।

कांग्रेस भ्रष्टाचार का खाया पचा रही: संघीय

रायपुर, 03 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस के संगठन चुनावों में हो रही दें को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस आज अजगर की भाँति सोहै पड़ा है और अपने शासनकाल के भ्रष्टाचार के माल को चाना में लगी है। कांग्रेस में पिछले डेढ़ वर्ष में न तो सदस्यता अधिकार चला, न ब्लॉक कमेटियों के चुनाव हुए हैं और उन्हीं घेस-पिटे प्रभावहीन जिला पदाधिकारियों से काम चला रही है। श्री शर्मा ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस में यह आलम है, जबकि दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के बाद भ्रष्टाचार ने सदस्यता अधियान चलाकर 60 लाख से अधिक सदस्य बनाये, बैथ, मंडल और नियुक्ति के चुनाव करने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रियंका गांधी देवे को पुनः चुन दिया। इसी लीच लोकसभा, नारीय निकाय चुनाव और त्रिसरीय पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत भी दर्ज की।

वक्फ संशोधन विधेयक ऐतिहासिक कदम; विकास मर्काम

रायपुर, 03 अप्रैल। भ्रष्टाचार अनुसूचित जनता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मर्काम ने केंद्र आदान-आदान द्वारा लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 की तारीफ करते हुए कहा यह विधेयक आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और संस्कृति सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक नियंत्रण है। यह विधेयक 5वीं और 6वीं अनुसूची श्वेतों में आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करता है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से रुक्खों देकर संस्कृतों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना किसी भी भूमि के वक्फ कार्यकृति के बिना किसी भी जिला के दायों में लाया गया है, जो फहले एक भौमिका भी व्यापिक समीक्षा से पैदा था। यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे देश की न्यायिक प्राप्ताली को मजबूती मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि भारत में वक्फ संपत्तियों की भी कानून के दायों में लाया गया है, जो फहले एक भौमिका भी व्यापिक समीक्षा से पैदा था। यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे देश की न्यायिक प्राप्ताली को मजबूती मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या अत्यधिक है और इसका समुचित उपयोग गरीब एवं जलसंतर्मद मुस्लिम समुदाय के लोगों तक किया जा सकता है। इसके अलावा, विधेयक में धारा 40 को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब कोई भी भूमि के वक्फ धारा 40 को लेकर करते हुए संख्यकारी अधिकारी अलग लहरी ने बताया कि लाभगत दो वर्ष से मंडी बोर्ड द्वारा नियंत्रित सकरी से धनसूती मार्ग की अधूरे सड़क नियंत्रण कार्य में लेटलतोंकी से प्रेषण है। सकरी के नारायणों का वाचन आवश्यक है। जिसके बाद से ही विगत 10 वर्षों से रिलायंस जियो से शुल्क वस्तु स्थगित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुंदर वर्मा ने कहा है कि केंद्रीय की जियो के लिये मोदी सरकार ने बीएसएनएल को तबाह कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार के बिना की वाचन आवश्यक है। सीजी ने ही अपनी रिपोर्ट में बताया है कि केंद्रीय बुद्धिमती ढांचा सेमेल करने का 1757 करोड़ 56 लाख रुपए शुल्क लहरी से रिलायंस जियो की दिशा में एक नियंत्रित सुधार है। तथा वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से हल करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्राप्त करता है।

अंबानी के निये मोदी सरकार ने बीएसएनएल को तबाह कर दिया

रायपुर, 03 अप्रैल। सोनीजी के रिपोर्ट में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल द्वारा मोदी राज में रिलायंस कंपनी को दी जी रही विधयत और अनुसूचित सुधार है। तथा वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से हल करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्राप्त करता है।

रायपुर, 03 अप्रैल। सोनीजी के रिपोर्ट में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। तथा वक्फ संपत्तियों की वाचन आवश्यक है। और परिषदों के विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ कार्यकृति के बिना की वाचन आवश्यक है। अब अन्य अधिकारों की ज्ञा सुनिश्चित करना है यह आदिवासियों के परंपरा में वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से क्षेत्रों को अशुण बनाए रखेगा। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में राज्यपाल और स्वायत्र परिषदों की विधिवाली के बिना की वाचन आवश्यक है। जिससे अब वक्फ क